जब कभी भी पानी में लकड़ी के बहुत सारे लट्ठे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे ''लॉगजैम'' कहते हैं। इस लॉगजैम से आसपास के जीवों को लाभ होता है। एक नए शोध से पता चला है कि लॉगजैम से सिर्फ मछलियों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि, अन्य जीव भी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। शोधकर्ता जानना चाहते थे कि, लॉगजैम और नदी में तैरती लकड़ी से जानवर किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। शोध के लेखक, ओरेगॉन स्टेट युनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इवान अरिसमेंदी ने कहा, हम जानते थे कि, नदियों में लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े पड़े होने से सामन फिश को फायदा होता है, पर अन्य वन्य जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में हमें बहुत कम जानकारी थी, इसलिए हम जानना चाहते थे कि अन्य जानवर इससे कैसे प्रभावित होते हैं। पूर्व में, लैंड मैनेजर्स यह सोचकर अक्सर ये लट्ठे हटा दिया करते थे, कि इससे जानवरों को नुकसान होगा। अरिसमेंदी कहते हैं, यह सोचकर कि, बाढ़ आने की स्थिति में लॉगजैम से ज्यादा नुकसान हो सकता है, लोग नदियों से लकड़ी के लट्ठे निकाल देते थे। इसके अलावा लट्ठों को नदी परिवहन में बाधा माना जाता था। फिर लोगों ने लॉगजैम के फायदे महसूस किए और 80 के दशक में नई शुरुआत हुई, धाराओं में लकड़ी के लट्ठे डालने की, अब इसपर हर साल लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ओरेगॉन में कोरवॉलिस से 15 मील पश्चिम में रॉक क्रीक के साथ-साथ 13 मोशन ट्रिगर्ड वीडियो कैमरे लगाए और जून 2021 से जून 2022 के बीच 1,921 वीडियो लिए जिनमें जानवरों की गतिविधियां दिख रही थीं। उन्होंने देखा कि 68 प्रतिशत वीडियोज़ में जो सबसे आम गतिविधि दिखी वह थी ''मूवमेंट'', 18 प्रतिशत में जानवर आराम करते हुए दिखे तथा 9 प्रतिशत में भोजन संबंधी गतिविधियां देखी गईं। शोधकर्ता लिखते हैं, ऑब्ज़र्वेशन्स से पता चलता है कि नदी में लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े कॉरिडोर की तरह काम करते हैं और वन्य जीवों की रेंज को आपस में जोड़ते हैं। शोधकर्ताओं ने इनमें स्तनपायी जीवों, मध्यम और बड़े आकार के परभक्षी, जलीय, स्थलीय पक्षियों व सैमीअक्वैटिक जानवरों की 40 प्रजातियां देखीं। उन्होंने गोल्डन ईगल भी देखा जो इस क्षेत्र में दुर्लभ है और म्यूल भी देखे जो नदी में बाढ़ आने पर सुरक्षा के लिए लकड़ी के लट्ठों पर चढ़ रहे थे। अरिसमेंदी ने कहा, ''हम हैरान थे कि इतनी सारी प्रजातियां लकड़ी के इन लट्ठों का इस्तेमाल कर रही थीं।'' बायोडायवर्सिटी जर्नल में छपे इस शोध में शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि, ये निष्कर्ष लैंड मैनेजर्स को बहते पानी में लकड़ी के लट्ठों की अहमियत समझा सकते हैं।

'चीन के मुद्दे पर प्र.मंत्री ने देश को गुमराह किया है'

एन.सी.पी. अध्यक्ष ने कहा कि, चीन सेना की घुसपैठ का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं यह केन्द्र की स्पष्ठ विफलता है

- **उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के रहते चीन ने भारतीय सीमा पर एलएसी का लगातार उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि, चीन की सेना अभी भी हमारे इलाके में जमी हुई है।**
- **अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सरकार पर हमला करते हुए पवार ने कहा कि, सरकार का दावा है कि, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो गयी है जबकि देश बहुत अधिक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सामना कर रहा है।उन्होने कहा कि केंद्र सरकार की गलत और तर्कहीन नीतियों के कारण आज महंगाई चरम पर है। वहीं रोजगार की समस्याओं के साथ-साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गयी हैं।**

नई दिल्ली 11 सितम्बर (वार्ता)। नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया है।

पवार ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राकांपा के आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया , लेकिन अब यह स्पष्ट है कि उन्होंने गलतबयानी की थी। उन्होंने जोर दिया कि चीन के मसले पर मोदी सरकार की विफलता स्पष्ट है।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के रहते चीन ने भारतीय सीमा पर एल.ए.सी. का लगातार उल्लंघन किया। हम चीनी घुसपैठ के सामने मुखर होकर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर यह हमारी विफलता नहीं है तो क्या है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सरकार पर हमला करते हुए पवार ने कहा कि सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो गयी है जबकि देश बहुत अधिक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार की गलत और तर्कहीन नीतियों के कारण आज महंगाई चरम पर है। वहीं रोजगार की समस्याओं के साथ-साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गयी हैं।

राकांपा नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के कुकर्मों को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जुटने के लिए तैयार रहने का आव्हान किया। उन्हेंने कहा विपक्षी एकता इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लोकतांत्रिक मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है, ऐसे में हमारे देश के युवाओं को आगे आना होगा। अब नयी पीढ़ी को लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार के कुकर्मों के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत है।

पवार ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा यह देश में अपने चरम पर है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय 410 रुपये में उपलब्ध एल.पी.जी. सिलैंडर के लिए अब 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं। पैट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इनके दाम बढ़ने से हर वस्तु की कीमत पर असर पड़ा है। खाद्य तेल, खाद्यान्नों और दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि आम आदमी इन्हें खरीदते वक्त पसीने-पसीने हो जा रहा है।

एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस साल 19 लाख युवाओं की नौकरियां दांव पर हैं।देश में 40 लाख नौकरियों के लिए 31 लाख पद फिलहाल खाली हैं, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण युवाओं की उपेक्षा की जा रही है।

अधिवेशन के लिए दिल्ली आये सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्होंने अपील की कि राकांपा को हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और उन ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना रही हैं।

सम्मेलन में राकांपा की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, योगानंद शास्त्री और अन्य क्षेत्रों के नेता उपस्थित रहे। इससे पहले राकांपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पवार को सर्वसम्मति से चार वर्षों के लिए फिर पार्टी अध्यक्ष चुना गया। वह 1999 से राकांपा के अध्यक्ष पद पर कायम हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सर्व पी.ए. संगमा और तारिक अनवर के साथ इस पार्टी का गठन किया था। करोना महामारी के कारण राकांपा राष्ट्रीय अधिवेशन दो वर्षों बाद हुआ है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को आगामी लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किये जाने से इन्कार करते हुए रविवार को कहा कि वह देश के हालात को देखते हुए विपक्ष की ओर से एक सशक्त भूमिका जरूर निभायेंगे।

राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के बाद संवाद-दाताओं से कहा कि पवार आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किये जायेंगे।

रूस को एक और मोर्चे पर यूक्रेन में मिली हार

यूक्रेन ने खारकीव से रूस के सैनिकों को वापस खदेड़ा

- **रूस की सरकार ने भी अपने सैनिकों को मुंह की खाने के बाद खारकीव से वापस लौटने का आदेश दे दिया है।**
- **भले ही रूस के इस मामले में अपने अलग तर्क हों, लेकिन उसका यह फैसला जंग का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। रूस के लिए मार्च में कीव गंवाने के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।**
- **यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक सप्ताह के भीतर ही खारकीव के इजियम शहर पर कब्जा जमा लिया था।**

कीव/मॉस्को, 11 सितम्बर। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को करारा झटका दिया है। दरअसल, यूक्रेनी सैनिक रूस के मजबूत कब्जे वाले खारकीव प्रांत के इजियम शहर में दाखिल हो गए हैं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने खारकीव से अस्थाई तौर पर अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। भले ही रूस के इस मामले में अपने अलग तर्क हों, लेकिन उसका यह फैसला जंग का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। रूस के लिए मार्च में कीव गंवाने के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।

यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक सप्ताह के भीतर ही खारकीव के इजियम शहर पर कब्जा जमा लिया था। इजियम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रसद मार्ग है। रूसी सैनिकों के यहां से पीछे हटने के ठीक बाद यूक्रेन ने यहां के कुपियांस्क रेलवे जंक्शन पर भी कब्जा जमा लिया। इससे रूस के लिए दोनाबास में रसद पहुंचाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इसके अलावा रूसी सैनिक बड़ी संख्या में यहां गोला-बारूद के भंडार और उपकरणों को भी छोड़कर वापस लौट गए। यह भी रूस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने इस महीने की शुरुआत से ही रूसी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद से लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर (770 वर्ग मील) क्षेत्र को मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रात में दिए संबोधन में कहा, हमारी सेना ने खारकीव में 30 से ज्यादा मोर्चों को फिर से कब्जे में ले लिया है। अब आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक द इस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार के अध्ययन के मुताबिक, इस हफ्ते शुरू हुए अभियान के तहत अब तक रूस को 2500 वर्ग किलोमीटर इलाके से खदेड़ा जा चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया है कि रूसी सेना को फिलहाल खारकीव क्षेत्र से अस्थायी तौर पर छोड़ने को कहा गया है। यहां बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना ने काफी आक्रामक ढंग से हमले किए हैं, जिनकी वजह से रूसी सेना को पीछे हटने का फैसला करना पड़ा है।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों के मुकाबले तीन गुना रिकवरी हुई रविवार को

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 160 नए संक्रमित मिले, वहीं 592 मरीज ठीक भी हुए हैं

- **इस बीच, जयपुर में 35 नए संक्रमित सामने आए हैं।**
- **प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 12 सौ से कम रहे गए हैं।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 11 सितम्बर। प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आने के साथ ही लगातार रिकवरी में बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य में रविवार को जहां 160 नए संक्रमित मिले, वहीं तीन गुना से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 1193 रह गए हैं।

प्रदेश में रविवार को 21 जिलों में 160 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 177 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में 35 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा अलवर में 15, अजमेर में 14, नागौर में 12, जोधपुर, प्रतापगढ़ व कोटा में 9-9, चित्तौड़गढ़, सिरोही व डूंगरपुर में 7-7, भरतपुर व धौलपुर में 6-6, बीकानेर में 5, उदयपुर में 4, दौसा, सीकर व जैसलमेर में 3-3, बारां व जालोर में 2-2, झालावाड़ व बाड़मेर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

प्रदेश में लगातार रिकवरी में बढ़ोत्तरी हो रही है। रविवार को एक ही दिन में 592 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस और घटकर 1193 रह गए हैं। जयपुर में भी पिछले चौबीस घंटों में 183 मरीजों के ठीक होने से 267 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं अलवर और जोधपुर ऐसे जिले है जहां सौ से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में रविवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9629 लोगों की मौत हो चुकी है।

जयपुर में रविवार को 16 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 मरीज मानसरोवर में मिले हैं। इसके अलावा सांगानेर में 5, वैशाली नगर में 4, जगतपुरा में 3, महेश नगर, मालवीय नगर व विद्याधर नगर में 2-2 तथा बनीपार्क, सिविल लाइन, दुर्गापुरा, जवाहर नगर, कोटपूतली, मुरलीपुरा, रामगंज और सोढ़ाला में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 3 संक्रमित का पता गलत मिला है।

लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर, 11 सितंबर (वार्ता)। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सोपोर उप जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए संगठन के लिए काम करने वाले चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।

एक पुलिस अधिकार ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस, सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (सी.आर.पी.एफ.) के जवानों ने गौसियाबाद चौक चिंकीपोरा में एक संयुक्त चौकी पर दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान दो व्यक्तियों को संदिग्ध गतिविधियों के कारण रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की। सतर्क सुरक्षा बलों ने हालांकि उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से दो हथगोले बरामद किए गए।

- **ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम किया करते थे। इनके पास से बरामद हथियारों चीन निर्मित एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 25 एके 47 राउंड, विस्फोटक सामग्री आदि शामिल है।**

दोनों की पहचान कुलोसा बांदीपोरा के शाकिर अकबर गोजरी और चिनाद बारामूला के मोहसिन वानी के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन लश्कर के लिए काम करते हैं। वे सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करने के अवसर की लगातार तलाश में थे।उन्होंने कहा, पकड़े गए आतंकवादियों ने जांच के दौरान अपने दो और सदस्यों के नामों का खुलासा किया। जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

द्वारका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूर्णिमा को शंकराचार्य ने दिए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी समेत कई गणमान्य हस्तियों ने शंकराचार्य के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

गैर अधिकृत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव प्रक्रिया केवल पार्टी को मजबूत करेगा।''

शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम और मनीष तिवारी सहित पांच सांसदों ने अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी थी। आपको बता दें कि कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।

कांग्रेस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरह की कार्रवाई न होने को लेकर भी निराशा जाहिर की है।

कमरुल इस्लाम ने लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया था। इसके बावजूद पार्टी द्वारा किसी तरह कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने लिखा है कि इसके चलते जमीन से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है।

फैक्ट्री में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा कि आग जल्द ही फैक्ट्री में फैल गई, जिसमें झुलसकर एक मजदूर की मौत हो गई।

सचिन जी.आई.डी.सी. के पुलिस निरीक्षक डी.वी. बलदानिया ने कहा कि देर रात शव बरामद किया गया।

'सबसे पहले राजभवनों का नाम बदलकर कर्तव्यभवन किया जाना चाहिये'

शशि थरूर ने राजपथ का नाम बदलने पर मोदी सरकार की आलोचना की

- **शशि थरूर का इशारा शायद प्रदेश की सरकारों एवं राजभवन के बीच टकराव की ओर था।**

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्यपथ करने पर भाजपा सरकार की जमकर आलोचन करते हुए कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर ने केंद्र से सवाल किया कि देश में सभी राजभवनों का नाम बदलकर कर्तव्यभवन क्यों नहीं होना चाहिए? ट्वीट करते हुए थरूर ने कहा कि सरकार को यहीं नहीं रुकना चाहिए बल्कि राजस्थान का नाम भी बदलकर कर्तव्यस्थान कर देना चाहिए।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद कहा था कि यह कदम तत्कालीन राजपथ से सत्ता का प्रतीक होने के नाते कर्तव्य पथ को सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण होने का प्रतीक है।

उन्होंने इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

कर्तव्यपथ का उद्घाटन करते हुए पी.एम. ने कहा था कि आज हम हम अतीत को पीछे छोड़ते हुए कल की तस्वीर को नए रंगों से भर रहे हैं। आज यह नई आभा हर जगह दिखाई दे रही है, यह नए भारत के विश्वास की आभा है। 'दास प्रथा का प्रतीक किंग्सवे (राजपथ), आज से इतिहास बनकर हमेशा के लिए मिटा दिया गया है', और मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।

आजादी के इस अमृतकाल में गुलामी की एक और पहचान से देशवासियों को आजादी मिल गई है' पी.एम. मोदी।

मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि कर्तव्यपथ केवल ईंटों और पत्थरों से बनी सड़क नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का एक जीवंत उदाहरण भी है।

मोदी का कहना था कि राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जो भारतीयों को गुलाम मानते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजपथ की भावना और संरचना गुलामी की प्रतीक थी, लेकिन आज वास्तुकला में बदलाव के साथ इसकी भावना भी बदल गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से राष्ट्रपति भवन तक फैला यह कार्तव्य पथ कर्तव्य की भावना से जीवंत होगा।

अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता। जो रायल्टी है। उतना पैसा लें। जितना पैसे लेते हैं। उसकी रसीद भी दें। 550 रुपए टन के हिसाब से ट्रक के पैसे ले रहे हैं। रॉयल्टी रसीद 40 रुपए के आसपास की दे रहे हैं।

मंत्री हेमाराम बोले बजरी के 10 गुणा ज्यादा ले रहे रुपए, रसीद काट रहे 45 रुपए की। चौधरी ने कहा तीन जगह खनन स्वीकृति के बाद भी रॉयल्टी 45 रुपए टन है। इसकी जगह 550 रुपए टन से ज्यादा लिए जा रहे हैं। जनता को लूटा जा रहा है। इसको लेकर मैंने मंत्री प्रमोद जैन भाया से बात भी कर ली है। इसको बंद किया जाए। इस लूट को हम होने नहीं देंगे।

बजरी माफिया को किसका सपोर्ट है। यह मेरे लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह तय कि बजरी मामले में जनता लुट रही है। मंत्री चौधरी ने बताया कि करीब एक माह पहले बजरी खनन को लेकर सी.एम. ने मीटिंग बुलाई थी। उसमें मैंने मंत्री को बता दिया था कि आम लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है। बाड़मेर में समदड़ी, बालोतरा, जाणियाणा और सिणधरी की लीज दी जाए। तब 1 सितंबर से समदड़ी, बालोतरा, जाणियाणा में बजरी खनन की स्वीकृति दी गई है। सिणधरी की लीज नहीं दी है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक हटा दी। करीब 4 साल बाद बजरी फिर से खुलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पिछले 8 माह तक अवैध बजरी माफिया जनता को लूट रहे थे।

इन बजरी माफियाओं से सिर्फ जनता ही नहीं, उनकी सरकार के मंत्री और विधायक भी दुखी हैं। सी.एम. अशोक गहलोत व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से भी जिले के सभी 6 कांग्रेसी विधायकों ने मिलकर बजरी खनन शुरू करने का मुद्दा उठाया। इसके बाद एक सितंबर से बाड़मेर में तीन लीज शुरू की गई इसके बाद भी 40 रुपए टन की बजाय 550 रुपए टन लोगों से लिया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर लेकर करीब एक माह पहले सी.एम. और मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में भी गुडामालानी विधायक हेमाराम चौधरी ने बजरी खनन शुरू करने और ठेकेदार की गुंडागर्दी और उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बावजूद भी बाड़मेर जिले की तीन बड़ी लीज हैं, जिन्हें बजरी खनन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। सरकार और ठेकेदार की सांठगांठ में बाड़मेर-जैसलमेर की जनता को लूटा जा रहा है। 10 हजार रुपए ट्रक मिलने वाली बजरी 20-25 हजार रुपए प्रति ट्रक बेची जा रही है। ठेकेदार अवैध वसूली कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।

एस.सी.ओ समिट में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तान जायेंगे

- **उज्बेकिस्तान में 15 सितम्बर से सम्मेलन शुरु होगा।**
- **प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे और दो दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे।**

नई दिल्ली, 11 सितम्बरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले दो दशकों में समूह की गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे और दो दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को होगा। इससे पहले जून 2019 में कर्गिस्तान के बिश्केक में एस.सी.ओ. सम्मेलन किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिखर सम्मेलन के अंत में एस.सी.ओ . की रोटेशनल प्रेसीडेंसी ग्रहण करेगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शिखर सम्मेलन में एस.सी.ओ. सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक देशों, एस.सी.ओ. के महासचिव, एस.सी.ओ. क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (आर.ए.टी.एस.) के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी एस.सी.ओ. के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए 15-16 सितंबर को समरकंद की यात्रा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं के पिछले दो दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और राज्य और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में आठ देश- चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। चार पर्यवेक्षक देश- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया संगठन की पूर्ण सदस्यता में शामिल होना चाहते है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908